राजाभाई अब्दुल रहमान मुंशी

बनाम

वासुदेव धनजीभाईभाई मोदी

1 मई, 1963

(ए.के.सरकार, एम.हिदायतुल्ला, जे.सी. शाह जेजे)

विशेष अनुमति-निरस्तीकरण-सर्वोच्च का अधिकार क्षेत्र कोर्ट ने विशेष अनुमति याचिका में दिया झूठा बयान-भारत का संविधान, अनुच्छेद 136

1954 में दायर एक मुकदमे में 1 अक्टूबर, 1954 को किरायेदार ने अदालत में रु. 400/- राशि जमा किया जो न्यायालय में 19 जनवरी, 1957 तक जमा रही, जब इसे वापस ले लिया गया। एक ताज़ा सूट किरायेदार को बेदखल करने के लिए सितंबर, 1955 में दायर किया गया था। 10 जनवरी 1957 को किरायेदार ने जमा रु. 400 राशि के बारे में गवाही दी लेकिन नौ दिनों के बाद इसे वापस ले लिया। सूट ख़राब था- 26 फरवरी, 1957 को ट्रायल कोर्ट द्वारा चूक गया आधार यह है कि अपेक्षित राशि जमा कर दी गई है न्यायालय में किरायेदार. निचली अपीलीय अदालत ने इसे स्वीकार कर लिया अपील की और इस आधार पर बेदखल करने का आदेश दिया कि राशि जमा किया रुपये पर्याप्त नहीं थे। 400/- की राशि पहले ही निकाली जा चुकी है। हाई कोर्ट में दायर पुनरीक्षण याचिका में यह दलील दी गई कि राशि रु. 400/- जमा थे और पर मकान मालिक का निपटान. हाई कोर्ट ने इस बात को स्वीकार कर लिया लेकिन इसके बावजूद उन्होंने इस मामले में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया पुनरीक्षण याचिका खारिज कर दी।

अपील करने के लिए विशेष अनुमति की याचिका में, किरायेदार के संबंध में उच्च न्यायालय के फैसले का एक लंबा उद्धरण उद्धृत किया गया- रुपये की जमा राशि डिंग। 400/- कोर्ट में जमा कर दिये उच्च न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचने में सही था क्योंकि याचिकाकर्ता के पास यह दिखाने के लिए रिकॉर्ड पर कुछ भी नहीं था की राशि 400/-किराया बकाया निकाल ली थी। याचिकाकर्ता नहीं था अपील करने की विशेष अनुमति दी गई,

अभिनिर्धारित कि, इसके द्वारा अपील करने की विशेष अनुमति दी गई कोर्ट को खाली कर देना चाहिए क्योंकि इसे खरीद लिया गया है अपीलकर्ता ने सभी भौतिक तथ्यों का खुलासा किए बिना। विशेष के लिए याचिका में जानबूझकर प्रयास किया गया था अपील करने के लिए छोड़ें न केवल अदालत से रोकें जानकारी है कि राशि रु. मूल रूप से 400/- रु अदालत में जमा की गई रकम बाद में उसके द्वारा वापस ले ली गई, लेकिन यह धारणा बनाने का भी गंभीर प्रयास किया गया वापसी के संबंध में उच्च न्यायालय का निष्कर्ष सही था।

प्रति सरकार और शाह जे.जे.- क्षेत्राधिकार का प्रयोग के अंतर्गत संविधान के अनुच्छेद 136 के विवेकाधीन है। यह है संयमित रूप से और असाधारण मामलों में प्रयोग किया जाता है जब कानून का महत्वपूर्ण प्रश्न निर्धारित किया जाना है या कहाँ हमें ऐसा प्रतीत होता है कि यह न्यायालय हस्तक्षेप कर रहा है गंभीर अन्याय को दूर करने के लिए आवश्यक है. एक पार्टी जो इस ओवर-राइडिंग का आह्वान करते हुए इस अदालत का दरवाजा खटखटाया जाता है विवेक स्वच्छ हाथों से आना चाहिए यदि वहाँ पर प्रकट होता है उसकी ओर से अदालत को आगे बढ़ाने या गुमराह करने का कोई भी प्रयास किया गया गलत या असत्य कथन या सत्य को छिपाकर वह जानकारी जिसका प्रश्न पर प्रभाव पड़ेगा विवेक का प्रयोग करते हुए न्यायालय को उचित ठहराया जाएगा

विवेक का प्रयोग करने से इंकार करना या यदि विवेक है यहाँ तक कि दी गई अपील की अनुमति को भी रद्द करने का प्रयोग किया गया अपील की सुनवाई के समय,

पर हिदावतुल्लाह जे - इसके द्वारा प्रयोग की जाने वाली शक्तियाँ संविधान के अनुच्छेद 136 के अंतर्गत न्यायालय में नहीं हैं सामान्य अपील की प्रकृति. वे इस न्यायालय को सक्षम बनाते हैं ऐसे मामलों में हस्तक्षेप करें जहां कोई अपूरणीय क्षति हुई हो गर्भपात के कारण हुआ (यदि न्याय सकल कारण से हुआ हो)। कानून या प्रक्रिया की उपेक्षा या अन्यथा और कोई नहीं है अन्य पर्याप्त उपाय. अनुच्छेद का शायद ही कोई मतलब हो ऐसे मामले में राहत प्रदान करें जहां एक पक्ष वह किराए का भुगतान करने में चूक कर रहा है क्योंकि उसने जमा राशि वापस ले ली है अदालत लेकिन जिसे मामले के रिकॉर्ड पर नहीं दिखाया जा सकता राशि निकाल ली है. वर्तमान मामला इनमें से एक नहीं है तथ्यों के वर्णन में मात्र त्रुटि या वास्तविक त्रुटि फैसले का. यह के साथ बेईमानी करने का मामला है न्यायालय ने एक अनुमान पर कानून का एक बिंदु बनाकर कहा उन तथ्यों के बारे में जिन्हें अगर खुलकर कहा जाए तो कोई गुंजाइश नहीं बचती कानून की चर्चा. अपीलकर्ता, इसमें असहमत होकर अदालत ने उसे एक मामले में विशेष अनुमति देने के लिए प्रेरित किया, जिसने ऐसा किया यह उचित नहीं है और इसलिए छुट्टी वापस ले ली जानी चाहिए।

हर नारायण बनाम बद्री दास। [1964] 2 एस. सी. आर. 203 और एस., बी. शेट्टी बनाम फ़िरोज़शाह नूरसेरवानजी कोलोबावाला और 1963 का एक और सी.ए. नं. 155, 5 अप्रैल 1963 को निर्णय लिया गया, अनुमत।

सिविल अपीलकर्ता क्षेत्राधिकार: सिविल-अपील संख्या 692/1962.

बम्बई उच्च न्यायालय दीवानी में का पुनरीक्षण आवेदन क्रमांक 139/1958 निर्णय और डिक्री से विशेष अनुमति द्वारा अपील दिनांक 20 जनवरी, 1960

जे. पी. मेहता, अजीज मुशब्बर अहमदी, जे. बी. दादाचंजी, अपीलकर्ता की ओर से ओ. सी. माथुर और रविंदर नारायण।

प्रतिवादी की ओर से विट्ठल बी. पटेल और आई. एन. श्रॉफ।

1 मई 1963. मे - सरकार और शाह का फैसला जे.जे. था शाह जे. द्वारा दिया गया, हिदायतुल्लाह, जे. ने अलग शाह. जे. निर्णय दिया.

जिन कारणों के बारे में हम वर्तमान में बताएंगे, उच्च के निर्णय के विरुद्ध अपील करने की विशेष अनुमति इस न्यायालय द्वारा दी गई बंबई की अदालत को खाली किया जाना चाहिए क्योंकि इसे अपीलकर्ता ने बिना खरीदे प्राप्त किया था सभी भौतिक तथ्यों का खुलासा करना।

राजाभाई मुंशी जिन्हें इसके बाद कहा जाएगा 'प्रतिवादी' 1935 से किरायेदार हैं वासुदेव मोदी को-इसके बाद 'योजनाकार' कहा जाएगा अहमदाबाद शहर में स्थित भूमि के एक टुकड़े का सम्मान। मूल रूप से निर्धारित भूमि का किराया रु। 411/- प्रति वर्ष, और इसे आपसी समझौते से बढ़ाकर रु. 1948 में 851/- प्रति वर्ष। वादी ने मुकदमा संख्या 2014 दायर किया 1952 में लघु वाद न्यायालय में प्रतिवादी के विरुद्ध एस के तहत क्षेत्राधिकार का प्रयोग करना। बॉम्बे रेंट्स के 28 और आवास गृह दरें (नियंत्रण) अधिनियम, 1947 (1947 का अधिनियम 57) याचिका पर प्रतिवादी के विरुद्ध निष्कासन का आदेश अन्य बातों के अलावा, बाद वाले ने भुगतान में चूक की थी उसके द्वारा देय किराया. प्रतिवादी ने अन्य बातों के साथ-साथ यह भी तर्क दिया निर्धारित किराया मानक किराए से अधिक था उसके द्वारा देय. ट्रायल कोर्ट ने मानक किराए का आकलन किया प्रतिवादी द्वारा देय रु. 446/प्रति वर्ष और होल्डिंग कि प्रतिवादी ने किराया चुकाने में कोई चूक नहीं की है, वादी का मुकदमा खारिज कर दिया. उस फरमान के खिलाफ वादी-वरीयता जिला के लिए 1953 की अपील संख्या 450

अहमदाबाद में न्यायालय. 1 अक्टूबर 1954 को प्रतिवादी जिला न्यायालय में जमा किये गये रु. 400/- का क्रेडिट वादी। वादी द्वारा अपील संस्थित की गई थी मुकदमा नहीं चलाया गया, और रुपये की राशि. 400/जमा कर दिया वादी का ऋण न्यायालय में जमा रहा।

वादी ने एक और कार्रवाई शुरू की (मुकदमा संख्या 3434/1955) प्रतिवादी के खिलाफ इस दलील पर कि प्रतिवादी ने किराए के भुगतान में नई चूक की थी। प्रतिवादी ने समय-समय पर न्यायालय में जमा किया 22 नवंबर, 1955 और 16 जनवरी, 1957 रु. 2,126/8/- की ओर उसके द्वारा देय किराया और मुकदमे की लागत। सीखा हुआ परीक्षण 26 फरवरी, 1957 के इस आदेश द्वारा न्यायाधीश ने यह निर्णय लिया खाते में रु. 400/- वादी के खाते में पड़े हुए हैं 1953 की अपील संख्या 450 में प्रतिवादी ने जमा किया था कोर्ट ने 2,526/8/- रूपये, और वह राशि पर्याप्त थी प्रतिवादी द्वारा देय किराये की बकाया राशि को भी पूरा करें मुकदमे की लागत, और इसलिए एस के मद्देनजर बेदखली में कोई डिक्री नहीं हो सकती। 12 (3) (बी) का 1947 का बॉम्बे एक्ट 57 मंजूर किया जाए।

अपील में अतिरिक्त सहायक न्यायाधीश, अहमदाबाद, ट्रायल कोर्ट के फैसले को पलट दिया। उनके विचार में प्रतिवादी बकाया किराये की पूरी राशि जमा करने में असफल रहा और एस द्वारा अपेक्षित सूट की लागत। 12 (3) (बी) और इसलिए बेदखली का डिक्री इसके खिलाफ जारी किया जाना चाहिए प्रतिवादी. द्वारा देय किराये का हिसाब-किताब बनाने में प्रतिवादी, विद्वान न्यायाधीश ने रुपये की राशि को बाहर कर दिया। 1 अक्टूबर 1953 को अपील संख्या 450/1953 में 400/- जमा किये गये। 1954, क्योंकि प्रतिवादी ने वह राशि पहले ही निकाल ली थी ट्रायल कोर्ट द्वारा मुकदमे का निपटारा कर दिया गया। के खिलाफ निष्कासन में डिक्री प्रतिवादी ने पुनरीक्षण का

आह्वान किया बम्बई उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार। उच्च न्यायालय के समक्ष प्रतिवादी का वकील तर्क दिया कि इसके समर्थन में कोई सबूत नहीं था अपीलीय न्यायालय का निष्कर्ष कि रु. 400/- 1953 की अपील संख्या 450 में प्रतिवादी द्वारा जमा किया गया प्रतिवादी द्वारा वापस ले लिया गया। हाई कोर्ट ने इसे बरकरार रखा विवाद लेकिन द्वारा दायर याचिका को खारिज करने के लिए आगे बढ़े प्रतिवादी क्योंकि मामला सख्ती से समझ में नहीं आया एस। 1947 के बॉम्बे अधिनियम 57 के 12 (3) (बी) और न्यायालय ने किया था क्षेत्राधिकार, परिस्थितियों और को ध्यान में रखते हुए किरायेदार का आचरण, उसे राहत देने से इंकार करना, और वह रिकॉर्ड से पता चला कि प्रतिवादी ने अपने आचरण से ऐसा किया था स्वयं को विवेकाधीन राहत से वंचित कर दिया। के खिलाफ उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश, विशेष अनुमति हेतु याचिका इस न्यायालय में अपील करने की अनुमति दी गई थी।

1947 के अधिनियम 57 की धारा 12 (1) प्रदान करती है:

> "एक मकान मालिक पुनर्भुगतान का हकदार नहीं होगा- जब तक किसी भी परिसर पर कब्ज़ा रहेगा किरायेदार भुगतान करता है, या तैयार है और इच्छुक है भुगतान करें, मानक किराए की राशि और अनुमत वृद्धि, यदि कोई हो, और निरीक्षण करता है और किरायेदारी की अन्य शर्तों को पूरा करता है, जहां तक कि वे के प्रावधानों के अनुरूप हैं यह अधिनियम;"

और उप-एस. (3) सी.एल. (बी) वह प्रदान करता है

> "किसी भी अन्य मामले में, बेदखली का कोई आदेश नहीं ऐसे किसी भी मुकदमे में पारित किया जाएगा, यदि, पर मुकदमे की सुनवाई का पहला दिन, या पर ऐसी अन्य तारीख से पहले, जो न्यायालय नियत

करे, किरायेदार भुगतान करता है या न्यायालय में निविदा डालता है मानक किराया और तब देय अनुमत वृद्धि और उसके बाद भुगतान या निविदा जारी रखता है कोर्ट ने नियमित रूप से ऐसे किराए की अनुमति दी मुक़दमे का अंतिम निर्णय होने तक बढ़ जाता है और के निर्देशानुसार सूट की लागत का भुगतान भी करता है न्यायालय."

यह सामान्य आधार है कि जो दावा किया गया है वादी विवरण के अंतर्गत आता है -'किसी अन्य मामले में'। हाई कोर्ट ने माना कि भले ही किरायेदार ने भुगतान नहीं किया हो अदालत में मानक किराया और अनुमत वृद्धि के कारण मुकदमे की सुनवाई के पहले दिन, अदालत अभी भी चल सकती है अपने विवेक का प्रयोग करते हुए किसी डिक्री को अस्वीकार कर देता है बेदखल करने वाले मकान मालिक ने किराए के सभी बकाया प्रदान किए और मुकदमे की लागत का भुगतान किरायेदार द्वारा न्यायालय को किया जाता है मुकदमे का निपटारा होने से पहले का समय इस प्रकार बनाई गई धारणा है तुरंत ही सत्य के बारे में कुछ सूक्ष्मता का प्रश्न उठाया एस की व्याख्या 12 (3) (बी)। हालाँकि यह प्रश्न हो सकता है उच्च के निष्कर्ष से ही पतन का निर्धारण किया जा सकता है अदालत ने कहा कि प्रतिवादी ने बकाया किराया जमा कर दिया है डिक्री पारित होने की तारीख से पहले मुकदमे की लागत ट्रायल कोर्ट सही हो. अपीलीय न्यायालय ने किया था दर्ज किया गया कि किराया बकाया था और मुकदमे की लागत नहीं थी प्रतिवादी द्वारा जमा किया गया, और इसलिए प्रतिवादी द्वारा उसके परिणामों से छुटकारा नहीं पाया जा सका गलती करना। जमा की गई रकम का हिसाब लेने में विद्वान न्यायाधीश ने रुपये की राशि को बाहर कर दिया। 400/- जमा कर दिया 1953 की अपील संख्या 450 जिसे वापस ले लिया गया था प्रतिवादी पर 19 जनवरी, 1957. हमारे सामने यह सामान्य बात है कि रु. 1953 की अपील संख्या 450 में प्रतिवादी द्वारा 400/ जमा किया गया वास्तव में डिक्री की तारीख से पहले उसके

द्वारा वापस ले लिया गया था ट्रायल कोर्ट का. प्रतिवादी के वकील यह स्वीकार करते हैं तथ्य, और यह प्रमाणित उद्धरण द्वारा समर्थित है जिला न्यायालय की फ़ाइल. उच्च के समक्ष सुनवाई में कोर्ट में प्रतिवादी के अधिवक्ता ने दलील दी कि अतिरिक्त सहायक न्यायाधीश का निष्कर्ष कि रु. ट्रायल कोर्ट का फैसला आने से पहले 400/- रुपये वापस ले लिए गए साक्ष्य द्वारा समर्थित नहीं. हम इसे धारण करने के लिए तैयार हैं की वापसी के संबंध में अधिवक्ता को निर्देश नहीं दिया गया था राशि, और उसके द्वारा न्यायालय को गुमराह करने का कोई प्रयास नहीं किया गया, और इस मामले में वकील को कोई दोष देने की आवश्यकता नहीं है उस ओर से प्रतिवादी रोक लगाने का दोषी था न्यायालय के साथ-साथ उनके वकील से भी जानकारी।

विशेष अनुमति के लिए याचिका में, जिसकी शपथ ली गई है प्रतिवादी ने न केवल जानबूझकर प्रयास किया है राशि की जानकारी न्यायालय से रोकना रुपये का - प्रतिवादी द्वारा मूलतः 400/- जमा किये गये थे उसके द्वारा वापस ले लिया गया है, लेकिन बहकावे में आकर सृजन करने का प्रयास किया गया है एक धारणा है कि उच्च न्यायालय का निष्कर्ष संबंधित है निकासी सही थी, और अतिरिक्त सहायक न्यायाधीश की गलत है, और यह तर्क देना कि जमा की गई रकम के कारण उसे रुपये सहित। प्रतिवादी 400/- का हकदार था उप-एसएस की सुरक्षा. (1) & (3) (बी) का एस. 12. एक नंगा याचिका के पैराग्राफ 14, 19, 20, 23 और 25 का अवलोकन विशेष अवकाश के लिए, इसमें संदेह की कोई गुंजाइश नहीं है कि यह था प्रतिवादी का उद्देश्य. में प्रस्तुत किया गया था याचिका कि प्रतिवादी का मामला सख्ती से दायरे में आता है एस की शर्तें 12(3)(बी) और यह कि उच्च न्यायालय से गलती हुई थी यह मानते हुए कि राहत देने से इनकार करने का उसके पास कोई विवेकाधिकार था प्रतिवादी द्वारा शर्तों का अनुपालन करने के बाद जमा के मामले में उस उपधारा की. याचिका प्रतिवादी द्वारा शपथ ली गई। उन्होंने पुष्टि की है पैराग्राफ । से 32 तक में बताए गए तथ्य उनके लिए

सत्य थे अपना ज्ञान और& उसमें दी गई दलीलों पर विश्वास किया गया उसके अनुसार सत्य है, और याचिका में कुछ भी नहीं छिपाया गया है न ही इसका कोई भाग मिथ्या या असत्य था। उन्होंने इसकी पुष्टि भी की उनका हलफनामा, कि उन्होंने "वकील को निर्देश दिया था।" नीचे के न्यायालय और वह" वह "इसमें परामर्शदाता को निर्देश दे रहा था विशेष अनुमति याचिका के संबंध में न्यायालय" तथ्य के प्रश्न पर उच्च न्यायालय का निष्कर्ष प्रतिवादी का ज्ञान ग़लत था, यह बनाया गया था जिसे एक महत्वपूर्ण प्रश्न माना गया था उसकी नींव सामान्य या सार्वजनिक महत्व के कानून का. यदि उच्च न्यायालय उस दृष्टिकोण को अपनाने के लिए राजी नहीं किया गया जो उसने किया था रुपये जमा करने का मामला 4001- आगे कोई प्रश्न नहीं होगा बच गए हैं; कम से कम n3one ऐसा प्रतीत होता है तर्क दिया।

वादी के वकील ने इस न्यायालय से आग्रह किया है यदि अपील करने के लिए विशेष अनुमति नहीं दी गई होती प्रतिवादी ने अदालत को सूचित किया था कि रुपये की राशि। 400/- जो कि क्रेडिट के लिए झूठ बोलना दर्शाया गया था वादी वास्तव में तारीख पर उपलब्ध नहीं था ट्रायल कोर्ट में डिक्री, क्योंकि सवाल यह है एस की व्याख्या 12(3)(बी) सही तथ्यों पर नहीं होगा गिरावट निर्धारित की जानी चाहिए, और विशेष अवकाश रद्द किया जाना चाहिए क्योंकि यह जानबूझकर गुमराह करके खरीदा गया है किसी महत्वपूर्ण मामले पर न्यायालय।

इस न्यायालय में अपील का सीमित अधिकार है सिविल मामलों में वादियों को संविधान द्वारा प्रदत्त। जहां विवादग्रस्त विषय-वस्तु की राशि या मूल्य प्रथम दृष्टया न्यायालय में और इसके विरुद्ध अपील में कोर्ट रुपये से कम नहीं है. 20,000/-, या जहां निर्णय, डिक्री या अंतिम आदेश में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कुछ शामिल होता है समान राशि की संपत्ति के संबंध में दावा या प्रश्न मूल्य, और निर्णय, डिक्री या अंतिम

आदेश हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच इसकी पुष्टि नहीं करती है ठीक नीचे न्यायालय का निर्णय, पीड़ित पक्ष अपील करने के अधिकार का हकदार है। एक प्रमाणपत्र के साथ नागरिक विवादों में भी अपील की जा सकती है अनुच्छेद के तहत उच्च न्यायालय। 133(1)(c)कि मामला सही है एक अपील के लिए, या अनुच्छेद के तहत छुट्टी के साथ। 136 का संवैधानिक उच्च न्यायालय ने प्रमाण पत्र नहीं दिया है अनुच्छेद के अंतर्गत। 133(1)(c)जैसा कि इसे देखते हुए नहीं किया जा सका सीएल में संवैधानिक निषेध. (3) का अनुच्छेद. 133. अनुच्छेद 133 के तहत न्यायालय के क्षेत्राधिकार का प्रयोग संविधान विवेकाधीन है: इसका प्रयोग संयमित ढंग से किया जाता है और असाधारण मामलों में, जब कानून का कोई महत्वपूर्ण प्रश्न हो निर्धारित किया जाना है या जहां यह न्यायालय को प्रतीत होता है गंभीर समाधान के लिए इस न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप आवश्यक है अन्याय. एक पक्ष जो इसका आह्वान करते हुए इस न्यायालय का दरवाजा खटखटाता है न्यायालय के इस सर्वोच्च विवेक का प्रयोग अवश्य होना चाहिए साफ हाथ लेकर आओ. यदि उसकी ओर से कोई प्रकट होता है झूठ या असत्य द्वारा न्यायालय तक पहुँचने या गुमराह करने का प्रयास बयान या सच्ची जानकारी रखने से जो होगा के अभ्यास के प्रश्न पर असर पड़ता है- क्रिएशन, पूर्व से इनकार करने में न्यायालय उचित होगा- विवेक का प्रयोग करें या यदि विवेक समाप्त हो गया है- में भी दी गई अपील की अनुमति को रद्द करने का निर्णय लिया गया अपील की सुनवाई का समय. हर नारायण बनाम बद्री दास ((1) [1964] 2 एस.सी.आर.203) में (1), गजेंद्रगडकर जे. की ओर से बोलते हुए। न्यायालय ने कहा:

> "सामग्री बनाने में यह अत्यंत महत्वपूर्ण है आवेदनों में कथन और आधार निर्धारित करना विशेष अवकाश, इस बात का ध्यान रखना होगा कि कोई बयानबाजी न हो जो ग़लत, असत्य या भ्रामक हैं."

उस मामले में न्यायालय ने दी गई छुट्टी रद्द कर दी क्योंकि अपीलकर्ता ने कुछ गलत और भ्रामक बातें कही थीं इस पर अपील करने की इजाजत के लिए उनकी याचिका में बयान अदालत। न्यायालय की दृष्टि में वे कथन थे, तथ्य की गलत बयानी और न्यायालय संतुष्ट कि अपीलकर्ता ने जानबूझ कर गुमराह किया है और असत्य कथन छुट्टी रद्द कर दी. एक अन्य मामले में जो लाया गया था यह न्यायालय विशेष अनुमति के साथ एस. आर. शेट्टी बनाम फ़िरोज़शाह नूरसेरवानजी कोलाबावाला (1) द्वारा एक प्रयास किया गया था विशेष अनुमति के लिए याचिका में अपीलकर्ता को महत्व देना होगा से अधिक की संपत्ति विवाद में है। 20,000/'- वास्तव में जब उन्होंने एक अन्य मुकदमे में उसी संपत्ति का मूल्य रु। 500/-. न्यायालय ने छुट्टी रद्द करते हुए कहा:

> "अपीलकर्ता ने जानबूझकर फुलाना चुना संपत्ति का मूल्यांकन ताकि प्राप्त किया जा सके विशेष छुट्टी. हमें इसमें कोई संदेह नहीं है कि अगर इस न्यायालय को सच्चाई से अवगत कराया गया था मूल्यांकन, जो अपीलकर्ता के अनुसार स्वयं मात्र रु. 500/-, यह न्यायालय करेगा विशेष अवकाश स्वीकृत नहीं किया है। हम इसलिए, इसे जानबूझकर माफ नहीं किया जा सकता के संबंध में न्यायालय को गुमराह करने का प्रयास बहुत ही भौतिक प्रश्न, अर्थात्, का मूल्य विवादग्रस्त संपत्ति."

प्रतिवादी के वकील ने स्वीकार किया है कि राशि रुपये का 400/- जो 1 अक्टूबर 1954 को जमा किया गया था फैसले की तारीख से पहले प्रतिवादी द्वारा वापस ले लिया गया ट्रायल कोर्ट. हालाँकि, उन्होंने तर्क दिया कि प्रतिवादी ने हाई कोर्ट में अपने वकील को उठाने का निर्देश नहीं दिया था रुपये की उपलब्धता को लेकर विवाद

400/से वादी, जिसे उच्च न्यायालय की मंजूरी मिली और यह विवाद अधिवक्ता द्वारा स्वयं उठाया गया था पहल वकील ने आगे कहा कि एक पक्ष आवेदन कर रहा है इस न्यायालय को विशेष अनुमति के लिए प्रतिबंधित करने का अधिकार है जो रिकॉर्ड पर और वर्तमान में दिखाई देता है, उसके प्रति स्वयं यदि प्रतिवादी ने निष्कर्ष सही ढंग से प्रस्तुत किया है उच्च न्यायालय और उस निष्कर्ष पर एक तर्क स्थापित किया है- प्रतिवादी के वकील की प्रस्तुति में निहित है सुझाव है कि किसी भी पार्टी के लिए उच्च को गुमराह करना खुला है न्यायालय या अधीनस्थ न्यायालय और उसके बाद इस पर संपर्क करें न्यायालय ने उसकी सामग्री संबंधी जानकारी को रोककर रखा ज्ञान जो होगा (1) 1963 का सी. ए. नं. 155, 5 अप्रैल 1963 को निर्णय लिया गया इस न्यायालय में जाने के उनके अधिकार को गंभीर रूप से प्रभावित किया उसके पक्ष में विवेक का प्रयोग। हम अधिक नहीं कर सकते- इस तथ्य पर जोर दें कि यह न्यायालय का क्षेत्राधिकार है विवेकाधीन. यह न्यायालय विशेष अनुदान देने के लिए बाध्य नहीं है केवल इसलिए छोड़ दें क्योंकि इसके लिए कहा गया है एक पार्टी जो संपर्क करती है न्यायालय यह जानते हुए या विश्वास करने का कारण रखते हुए कि यदि सही तथ्य उसके संज्ञान में लाए जाएं, यह न्यायालय ऐसा नहीं करेगा उस जानकारी को ध्यान में रखते हुए विशेष अवकाश प्रदान करें इस न्यायालय को अपील करने की अनुमति देने के लिए राजी करना दोषी है विवेक के प्रयोग के सभी दावों को त्यागने वाला आचरण उसके पक्ष में. तथ्यों को बताना उसका कर्तव्य है जो हो सकता है के अभ्यास पर यथोचित प्रभाव पड़ता है- इस न्यायालय की रचनात्मक शक्तियों को रोकने का कोई भी प्रयास सामग्री संबंधी जानकारी के परिणामस्वरूप इसे रद्द कर दिया जाएगा आदेश, इस न्यायालय से प्राप्त हुआ। हम सहमत होने में असमर्थ हैं प्रतिवादी के वकील के साथ कि आवेदक का कर्तव्य इस न्यायालय को विशेष अनुमति के लिए तब छुट्टी दे दी जाती है जब वह केवल नीचे दिए गए न्यायालयों के निर्णय और दावों का सारांश प्रस्तुत

करता है इस आधार पर राहत कि निष्कर्ष सही हैं, कब करें उसके ज्ञान के निष्कर्षों को बरकरार नहीं रखा जा सकता है और निष्कर्ष इसलिए दर्ज किए गए हैं क्योंकि नीचे के न्यायालयों ने ऐसा किया है के निर्माण के लिए अभ्यावेदन के कारण गुमराह किया गया है जिसके लिए वह प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जिम्मेदार था। में हमारा निर्णय इस न्यायालय के समक्ष दायर याचिका पर था भ्रामक.

प्रतिवादी के वकील ने यह भी कहा कि था उच्च स्तर पर अपील पर बहस करने के लिए तैयार न्यायालय ने जिले के फैसले को पलटने में गलती की रुपये की निकासी के सवाल पर कोर्ट 4001-. यदि, तथापि, प्रतिवादी ने न्यायालय को गुमराह किया है विशेष अवकाश देने का आदेश प्राप्त किया और उसके अधीन है उस आदेश की सुरक्षा उसी के कब्जे में रही तीन साल की अवधि के लिए विवादित संपत्ति होगी प्रतिवादी के अनुचित आचरण पर प्रीमियम लगाना ताकि उसे अपील पर किसी अन्य आधार पर बहस करने की अनुमति दी जा सके जिस पर मुकदमे की बहस हुई उच्च न्यायालय में, और बहस करने के लिए जो संभवतः कोई विशेष नहीं है छुट्टी मिल गई होगी. इसलिए अपील करने की विशेष अनुमति रद्द की जाती है। अपीलकर्ता प्रतिवादी को अपील की लागत का भुगतान करेगा। हिदायतुल्ला जे.---मैं सहमत हूं कि हमें इसे वापस लेना चाहिए विशेष अवकाश। चूँकि यह कुछ ही दिनों में दूसरा मामला है, मैं कुछ शब्द कहना चाहता हूँ. हमारे समक्ष अपीलकर्ता है किरायेदार और प्रतिवादी मकान मालिक है। में से एक मामले में सवाल यह था कि क्या किरायेदार डिफ़ॉल्टर था उसके द्वारा विशेष रूप से देय किराया और राजस्व कर का। यह ऐसा प्रतीत होता है कि पार्टियों के बीच मुकदमा चल रहा है वर्षों तक. मकान मालिक को मुकदमा दायर करने के लिए मजबूर होना पड़ा इस आधार पर बेदखली कि किरायेदार ने भुगतान नहीं किया था किराया। किरायेदार ने भी अदालत के अलावा कभी किराया नहीं दिया। में पहले के दौर में,

किरायेदार सफल रहा है अंतिम क्षण में किराया और लागत जमा करना, इस प्रकार लेना 1947 के बॉम्बे अधिनियम LVII का लाभ।

ऐसा प्रतीत होता है कि मकान मालिक का ऐसा ही एक मुकदमा नं. 2014/1952, डिक्री से उत्पन्न अपील के दौरान वह मुकदमा, किरायेदार ने 1 अक्टूबर 1954 को जमा किया था रुपये की राशि 400/- की अपील कोर्ट में की और नोटिस भेजा था इस जमा राशि के बारे में मकान मालिक को। यह जमा राशि पड़ी 19 जनवरी, 1957 तक अदालत में, जब इसे वापस ले लिया गया। अंतिम तिथि महत्वपूर्ण है.

वर्तमान मुकदमा 8 सितंबर 1955 को दायर किया गया था बकाया होने के आधार पर किरायेदार को बेदखल करना 9 जून, 1953 से। 10 जनवरी, 1957 को किरायेदार ने पदच्युत कर दिया जमा राशि के बारे में मकान मालिक से पूछताछ की नोटिस, लेकिन केस ख़त्म होने से पहले ही उन्होंने वापस ले लिया जमा करना। विद्वान न्यायाधीश, लघु वाद न्यायालय, अहमदाबाद, मकान मालिक के खिलाफ उप-किराए पर देने की बात रखी, और आगे भी पकड़े रहना कि रुपये की जमा राशि. 2126/8/- किरायेदार द्वारा अपने में बनाया गया अदालत बकाया राशि को कवर करने के लिए पर्याप्त थी, और वह ले ली गई रुपये की जमा राशि के साथ. 4001., राशि रु. 2516/8/- मुकदमा खारिज कर दिया। यह 26 फरवरी 1957 की बात है.

मकान मालिक द्वारा दायर अपील में, खाते 9-6-1953 के बीच 26-2-1957 को पुनः बनाया गया। यह लगता है कि यह अपील अदालत को बताया गया कि किरायेदार के पास था रुपये की जमा राशि निकाल ली. 400/-. ये हुआ फैसला तथ्य को ध्यान में रखा और किरायेदार को बकाया माना और उसे बेदखल करने का आदेश दिया. किरायेदार ने एक पुनरीक्षण दायर किया उच्च न्यायालय में आवेदन किया और दावा किया कि यह राशि कितनी है रुपये का 400/- जमा राशि थी और मकान मालिक के

पास थी, उसे चूककर्ता नहीं ठहराया जा सकता। उनके वकील ने बनाया इंगित करें कि यह साबित करने के लिए रिकॉर्ड पर कुछ भी नहीं था राशि निकाल ली गयी. उच्च न्यायालय ने माना कि ऐसा ही था लेकिन यह माना कि इस मामले में उसका विवेकाधिकार था किरायेदार ने वर्षों से अपने आचरण से स्वयं को वंचित कर लिया था कोई विचार. पुनरीक्षण हेतु आवेदन था बर्खास्त.

आदेश के विरूद्ध विशेष अवकाश हेतु आवेदन करने में उच्च न्यायालय, किरायेदार ने एक लंबा उद्धरण उद्धृत किया उच्च न्यायालय का निर्णय जहां उसने इस जमा राशि की बात की, और फिर कहने लगा:

> "याचिकाकर्ता का कहना है कि उच्च कोर्ट निष्कर्ष पर पहुंचने में सही था चूँकि दिखाने के लिए रिकॉर्ड पर कुछ भी नहीं था याचिकाकर्ता ने यह राशि वापस ले ली है रु. उसके द्वारा पूर्व में 400/- रूपये जमा किये गये थे अपील, याचिकाकर्ता पर बकाया नहीं था की तारीख पर किराया और लागत का भुगतान किया था निर्णय.''

इस आरोप का समर्थन सामान्य हलफनामे द्वारा किया गया था कहा गया कि याचिका में तथ्य सत्य थे और याचिका में कुछ भी नहीं छिपाया गया। कठोरता से बोलते हुए, तथ्य वैसे ही थे जैसे उन्हें बताया गया था याचिका, लेकिन और भी बहुत कुछ था। एक तथ्य था विशेष रूप से किरायेदार की जानकारी में था और यह था उन्होंने यह रकम 19 जनवरी 1957 को निकाली थी और उन्होंने की अदालत के फैसले से पहले भी डिफॉल्ट में था पहला उदाहरण 26 फरवरी, 1957 को दिया गया था। यह तथ्य हालाँकि, मामले के रिकॉर्ड पर यह साबित नहीं हुआ था। वह था, हालाँकि, अपील अदालत के फैसले में इसका उल्लेख किया गया है। में विशेष अनुमति के लिए याचिका में इस तथ्य का कोई संदर्भ नहीं बनाया गया था। क्या उच्च न्यायालय एक मामले में

सही था? रिकॉर्ड के अनुसार, या अपील किस प्रकार की है, इसे ध्यान में रखते हुए निचली अदालत ने कहा था, हो सकता है कि उसने हलफनामा मांगा हो निर्णय लेना आवश्यक नहीं है और मैं इसके बारे में कोई राय व्यक्त नहीं करता हूँ यह। हालाँकि, जब हम आते हैं तो यह बहुत अलग मामला होता है इस न्यायालय में कार्यवाही. किरायेदार विशेष चाह रहा था उच्च न्यायालय के आदेश के विरुद्ध छुट्टी. सबसे आगे इस याचिका में उन्होंने इस तथ्य का उल्लेख किया था कि उच्च कोर्ट ने माना कि वापसी का कोई सबूत नहीं था किरायेदार द्वारा या याचिकाकर्ता द्वारा की गई राशि का बकाया. विवेक का प्रयोग करना चाहिए था, जो उच्च न्यायालय ने उसके पक्ष में फैसला सुनाया।

किरायेदार ने फैसले से पहले ही यह बात छिपा ली प्रथम दृष्टया अदालत में" वह बकाया राशि में था जैसा कि उसके पास था की राशि निकाल ली। 400/-. वह इस प्रकार ले रहा था अदालत में एक काल्पनिक जमा का लाभ जो बिंदु में है तथ्य अस्तित्व में नहीं था. इसके बारे में कुछ भी कहा जाए मुकदमेबाजी की सामान्य प्रक्रिया जिसमें पक्ष सफल होते हैं या रिकॉर्ड पर पर्याप्तता या अन्यथा सबूत पर असफल, मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि जब कोई पक्ष इस न्यायालय का दरवाजा खटखटाता है अनुच्छेद 136 के अंतर्गत, उसकी ओर से पूरी स्पष्टवादिता होनी चाहिए। अनुच्छेद के तहत इस न्यायालय द्वारा प्रयोग की जाने वाली शक्तियाँ। 136 का संविधान सामान्य अपील की प्रकृति में नहीं है। वे इस न्यायालय को उन मामलों में हस्तक्षेप करने में सक्षम बनाते हैं जहां के कारण अपूरणीय क्षति हुई है के कारण न्याय का गर्भपात कानून या प्रक्रिया या अन्यथा की घोर उपेक्षा कोई अन्य पर्याप्त उपाय नहीं है. लेख शायद ही इसके लिए अभिप्रेत है इस प्रकार के मामले में राहत प्रदान करें जहां कोई पक्ष शामिल हो किराए का भुगतान न करना क्योंकि उसने अदालत में पड़ी जमा राशि वापस ले ली लेकिन जो मामले के रिकॉर्ड पर नहीं दिखाया जा सकता है राशि निकाल ली. यदि याचिका में इसका उल्लेख किया गया था अपील अदालत का निर्णय आधार

पर आगे बढ़ा था वह' कितनी रकम निकाली गई, इसका अंदाजा लगाना मुश्किल है कि इस न्यायालय ने निर्णय लेने के लिए विशेष अनुमति दी होगी विवेक का प्रश्न.

मैंने मामले पर ध्यानपूर्वक विचार किया है. यह नहीं है एक तथ्यों के वर्णन में मात्र त्रुटि या प्रामाणिकता का मामला निर्णय की त्रुटिपूर्ण त्रुटि जो कुछ परिस्थितियों में हो सकती है शिरापरक दोष माना जाता है। यह होने का मामला है कानून का मुद्दा बनाकर न्यायालय के साथ बेईमानी की गई है एक अनुमान तथ्यों की स्थिति, कौन सा तथ्य, यदि बताया जाए स्पष्ट रूप से, कानून की चर्चा के लिए कोई जगह न छोड़ें। अपीलकर्ता ने इस न्यायालय में असहमति जताते हुए इसे प्रेरित किया है ऐसे मामले में विशेष अनुमति देना जो उचित नहीं था। मैं इसलिए, सहमत हूं कि इस छुट्टी को वापस ले लिया जाना चाहिए और अपीलकर्ता को इस अपील की लागत का भुगतान करने के लिए कहा गया।

विशेष अनुमति निरस्त की गई।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण : यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिएए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।